(d) and (e) Government has worked out an attractive package of terms and conditions for encouraging risk capital investment in exploration and subsequent production. Discovered oil and gas fields have also been offered for development by private companies under joint venture arrangements for medium sized fields and under production sharing contract for small sized fields.

To increase indigenous production of petroleum products, efforts are being made to increase he refinding capacity by taking up expansion of existing refineries and setting up if new grassroot refineries in the pubilc sector, joint venture and private sector besides promoting conservation of petroleum products in various fields. Through conservation measures, it has been possible to achieve a quantifiable savings of about Rs. 950.40 crores and Rs. 1174.88 crores during 1992-93 and 1993-94 respectively.

असत्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर खोली गई रसोई गैस एजेंसियों का चलना जारी रहना

1239. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन रसोई गैस एजेंसियों को चलाना जारी रखने की अनुमति दे रही है जिनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उन एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके अनुसूचित/जाति अनुसूचित जनजाती के प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई थी ;

(घ) 30 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार कितने मामलों की जांच पूरी हो गई है और कितने मामले न्यायाधीन है ; और

(ङ) जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ङ) पिछले 5 वर्षों के दौरान 6 मामलों में चयनित डिस्ट्रीब्यूटरों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता को चुनौती दी गई है । एक मामला [illegible] न्यायालय, नागपुर खंडपीठ में लंबित है और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को प्रचालन करने की अनुमति दी जा रही है। दो मामलों में डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को समाप्त कर दिया गया है। बाकी के 3 मामलों में चुने हुए डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध आरोप वापस लिए गए है, क्योंकि उनके जाति प्रमाणपत्र की पुष्टि उच्च न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है ।

Chartering of off-shore supply vessels by ONGC

1240 DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Operators of Off-shore Supply Vessels (OSVs) have deserted the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), if so, what are the reasons therefor;

(b) what were the details of the terms and conditions on which OSVs were chartered; and

(c) what are the details of the steps Government have taken to avert the situation?